

भारत में सांप्रदायिकता (Communalism in India)

सांप्रदायिकता का अर्थ (Meaning of Communalism)

सांप्रदायिकता मस्तिष्क की वह प्रवृत्ति है, जिसके अंतर्गत एक धार्मिक समूह के समर्थक अपने आपको एक पृथक सामाजिक राजनीतिक इकाई मानते हुए दूसरे समूह को अपने विरोधी हितों वाला समूह मानते हैं।

किसी धर्म के प्रति आस्था या धार्मिक व्यवस्था का अनुगमन सांप्रदायिकता नहीं कहा जा सकता बल्कि धर्म का शोषण करना सांप्रदायिकता है। एक धार्मिक समुदाय को दूसरे समुदाय के विरुद्ध तथा राष्ट्र की संयुक्तता के विरुद्ध उपयोग किया जाना सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता वस्तुतः धार्मिकता को राजनीतिक शत्रुता में बदलने की प्रक्रिया है जो प्रगति, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्ष संस्कृति, तार्किकता एवं वैज्ञानिकता का विरोधी है। साम्प्रदायिक व्यक्ति के लिए राजनीति एवं राज्य के मामलों में धार्मिक समुदाय ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है। इस आधार पर सांप्रदायिकता राष्ट्रवाद की विरोधी प्रक्रिया है जिसमें बहुल नृजातीय, धार्मिक एवं भाषायी समुदायों को एकीकृत करने की बजाय विखंडित करने की रणनीति अपनायी जाती है। इसमें सामाजिक- सांस्कृतिक सहअस्तित्व एवं राजनीतिक समन्वय की विचारधारा का विरोध सन्निहित है।

सांप्रदायिकता धर्म और राजनीति का एक अपवित्र समझौता है जिसकी अभिव्यक्ति दो रूपों में परिलक्षित होती है-

1. धार्मिक उद्देश्यों के लिए राजनीतिक शक्ति का उपयोग किया जाना तथा
2. राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का उपयोग किया जाना।

सांप्रदायिकता की प्रक्रिया में धर्म का उपयोग आत्म परिपूर्णता के लिए नहीं वरन् एक विशेषाधिकारयुक्त अस्त्र के रूप में राजनीतिक शक्ति हासिल करने के लिए किया जाता है।

इन परिभाषाओं के आधार पर सांप्रदायिकता की निम्नलिखित विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं:-

सांप्रदायिकता की विशेषताएँ (Characteristics of Communalism)

1. सांप्रदायिकता एक मनःस्थिति अथवा मन की प्रवृत्ति है। सांप्रदायिकता की प्रवृत्ति में प्रत्येक धार्मिक समूह को एक पृथक सामाजिक राजनीतिक इकाई के रूप में देखा जाता है।

2. इसके अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक समूह दूसरे समूहों के प्रति प्रतिद्वंद्विता एवं वैर का भाव रखता है।
3. सांप्रदायिकता में धर्म का शोषण किया जाता है अर्थात् एक धार्मिक समुदाय को दूसरे धार्मिक समुदाय के विरुद्ध उपयोग किया जाता है।
4. सांप्रदायिकता में राजनीतिक आकांक्षा (Political Aspiration) एवं क्रिया हेतु धार्मिक समुदाय को ही समग्र के रूप में स्वीकारा जाता है।
5. सांप्रदायिकता विभिन्न समूहों को जोड़ने एवं तोड़ने की एक राजनीतिक रणनीति है।
6. सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता एवं प्रजातंत्र के आधार पर राष्ट्रीय एकीकरण एवं राजनीतिक व्यवस्था की विरोधी प्रक्रिया है।
7. सांप्रदायिकता एक विशेषाधिकार युक्त अस्त्र है जिसमें राजनीति एवं धर्म के अपवित्र गठबंधन के आधार पर शक्ति हासिल की जाती है। वस्तुतः यह नृजातीय अस्मिता (Ethnic Identity) एवं आधुनिक हितों (स्वार्थों) का एक विलक्षण संयोजन है।

भारत में सांप्रदायिकता (Communalism in India)

दो समुदायों के मध्य भाषा, जाति व अन्य नृजातीय तत्वों के आधार पर व्याप्त घृणा, विद्वेष या संघर्ष की मनोवृत्ति को सांप्रदायिकता कहते हैं, जिसको भारत में मुख्यतः धर्म के संदर्भ में देखा जाता है।

नई आर्थिक नीति व वैश्वीकरण की छाया में सांप्रदायिकता का विस्फोट भारत में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का एक प्रमुख अभिलक्षण (Characteristics) बन गया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड, गोधरा कांड के परिणामस्वरूप संपूर्ण भारत व गुजरात में फैला दंगा तथा पंजाब में अकाली दल और डेरा सच्चा सौदा के मध्य तनाव तथा मुजफ्फरनगर दंगा ने साम्प्रदायिक तनाव को ज्वलंत मुद्दा बना दिया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में सांप्रदायिकता उन्मूलन को दी गई प्राथमिकता राष्ट्र के समक्ष सांप्रदायिकता की गंभीरता को परिलक्षित करती है।

भारत में सांप्रदायिकता के कारण (Causes of Communalism in India)

भारत में साम्प्रदायिक तनाव का बीजारोपण मुस्लिम आक्रमणों और मुस्लिम शासनकाल में ही हो गया था परंतु इसे सम्पुष्ट (Solid) करने वाले कारकों को निम्न रूप में देखा जा सकता है:-

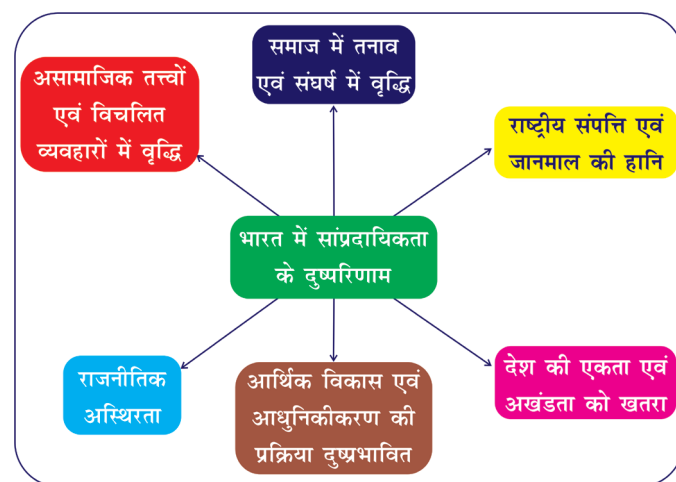
1. अंग्रेजों की 'फूट डालो और राज करो' की नीति ने हिन्दू-मुस्लिम दोनों समुदायों के मध्य विद्वेष को तीव्र कर दिया, जिसका परिणाम भारत का विभाजन और 1946-48 के दंगों में लगभग 2 लाख लोगों की मौत के रूप में सामने आया।
2. 1947 के बँटवारे के बाद भारतीय मुस्लिमों में पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति (जो कि स्वाभाविक थी) से भारत के हिन्दू जनमानस में भ्रामक संदेश गया, जिसने उनके मन में मुस्लिमों के प्रति अविश्वास को पुष्ट किया।
3. शाहबानो प्रकरण ने दोनों समुदायों में परस्पर अविश्वास एवं विद्वेष को और बढ़ा दिया। शाहबानों के मामले में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को नहीं माना तथा साम्प्रदायिक दबाव के कारण मुस्लिम महिला विधेयक पारित करवाया। परिणामस्वरूप हिन्दू कट्टरपंथी संस्थाओं ने भी राम जन्म भूमि विवाद पर न्यायालय के नकारात्मक फैसला आने की स्थिति में मानने से मना कर दिया।
4. स्वार्थी राजनीतिक दलों, नेताओं एवं असामाजिक तत्वों ने अपने स्वार्थों की सिद्धि हेतु इसको कम करने के बजाए इसे बढ़ाने का प्रयास किया (मुजफ्फरनगर दंगों, केरल, कर्नाटक के 2004 के दंगे, गोधरा दंगा, मुंबई दंगे)। श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है।
5. धार्मिक कट्टरपंथियों (Religious Fundamentalist) द्वारा अपने-अपने समुदायों को धर्म रक्षा के नाम पर एक-दूसरे के विरुद्ध भड़काया जा रहा है। कट्टरपंथियों द्वारा अपने समुदाय में हिन्दू खतरे में, इस्लाम खतरे में जैसे-नारों के द्वारा डर फैलाया जाता है। इससे दूसरे समुदाय के प्रति विरोध एवं कटुता तीव्र होती है।
6. मुस्लिमों द्वारा परिवार नियोजन नहीं अपनाया जाना भी हिन्दुओं में उनके प्रति संदेह और द्वेष को बढ़ाया है। हिन्दू कट्टरपंथियों द्वारा इसको मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ाकर भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की रणनीति के रूप में प्रचारित किया जाता है।
7. सरकार की तुष्टीकरण की नीति ने भी विभिन्न समुदायों को उद्वेलित किया है। वोट बैंक की राजनीति के तहत विभिन्न राजनीतिक दल द्वारा एक विशेष समुदाय हेतु योजनाएँ एवं कार्यक्रम का लाया जाना अन्य समुदाय में विद्वेष की भावना पैदा करती है।
8. कानून लागू करने वाली एंजिसियों के सम्प्रदायीकरण (वी. एन. राय का परसेप्शन ऑफ पोलिस न्यूट्रालिटी इन कम्यूनल राइट्स) ने स्थिति को और गम्भीर बनाया है।
9. वैश्वीकरणजनित पहचाना संकट के समाधान के क्रम में धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद एवं धार्मिक रूढ़िवाद में वृद्धि हुई है। इस प्रक्रिया ने भी धार्मिक समुदायों के मध्य संदेह एवं विद्वेष की भावना में वृद्धि की है। 2002 में गुजरात में हुए दंगों के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा लूटपाट एवं बलात्कार

- की वीभत्स घटनाओं में असामाजिक तत्वों की भूमिका देखी जा सकती है। इसी तरह 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में भी असामाजिक तत्वों की व्यापक भूमिका देखी जा सकती है।
10. वोट बैंक की राजनीति के अंतर्गत धार्मिक समुदायों के मतों का ध्रुवीकरण (Vote Polarization) हेतु भी दंगे एवं तनाव का वातावरण पैदा किया जाता है। हाल ही में हुए मुजफ्फरनगर दंगों को इसके उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।
 11. धर्मांतरण एवं पुनः धर्मांतरण के मुद्दे के राजनीतिकरण ने भी संप्रदायवाद की उत्पत्ति एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ओडिशा के कंधमाल के हुए दंगों को इसके उदाहरण स्वरूप देखा जा सकता है।
 12. सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक विसंगतियाँ भी ऐसे परिवेश का निर्माण करती हैं जो कि सम्प्रदायवाद के लिए उत्तरदायी होते हैं। कृषि मंत्रालय के एक शोध रिपोर्ट के अनुसार हिन्दी भाषी क्षेत्र में 50% प्रतिशत अतिरिक्त भूमि का सही वितरण न हो पाना साम्प्रदायिकता में बढ़ोतरी का एक महत्वपूर्ण कारक है।

इनके अतिरिक्त कई अन्य कारक, यथा-गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, मीडिया की नकारात्मक भूमिका, हाल में उभर रहे धार्मिक कट्टरवाद, पड़ोसी देशों द्वारा प्रोत्साहन, संस्कृति तथा रीति-रिवाजों में भिन्नता आदि भी सांप्रदायिकता के पोषक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत में सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम (Consequences of Communalism in India)

भारत एक बहुलवादी समाज (Pluralistic Society) है जहाँ विभिन्न धर्मावलम्बी रहते हैं। समाज में अपने अस्तित्व एवं स्वतंत्र पहचान कायम रखते हुए भी एक-दूसरे के साथ इनकी सामाजिक अंतःक्रिया (Social Interaction) होती रही है जो कि प्रायः समाज के संदर्भ में सकारात्मक रही है, जिसके कारण ही भारतीय समाज एक बहुरंगी धार्मिक एवं सांस्कृतिक छवि वाले समाज के रूप में देखा एवं समझा जाता रहा है।



किंतु वर्तमान में विविध कारणों के परिणामस्वरूप भारत के इन विविध धर्मावलम्बियों के अंतःक्रिया का स्वरूप नकारात्मक हो रहा है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के दुष्प्रभाव समाज में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उन दुष्प्रभावों की चर्चा निम्न रूप में की जा सकती है:-

1. समाज में तनाव एवं संघर्ष में वृद्धि (Increase tension and Conflict in Society) – भारत में विविध साम्प्रदायिक समूह एक-दूसरे के साथ सामाजिक संबंध बनाने से बचते ही नहीं बल्कि एक-दूसरे को संदेह की दृष्टि से भी देखते हैं। विभिन्न सम्प्रदाय के लोग सभाओं एवं समाचार पत्रों के माध्यम से एक-दूसरे का छिन्दान्वेषण (Hole exploration) करते हैं तथा उनके व्यक्तिगत विचारों एवं व्यवहारों को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसके कारण इनमें तनाव एवं संघर्ष पैदा होता है, भारत में विविध हिन्दू एवं मुस्लिम त्यौहारों के समय ऐसा अक्सर देखा जाता है, ताजिया निकालते समय अथवा होली एवं दशहरे के त्यौहारों पर अंतर्सामुदायिक (Inter community) संघर्ष अक्सर देखे जा सकते हैं।

2. राष्ट्रीय संपत्ति एवं जानमाल की हानि (Loss of National Property and Life) – साम्प्रदायिक संघर्ष के दौरान भारत में अक्सर जान माल का नुकसान होता है, चाहे भारत-पाक बंटवारे के समय हो अथवा विविध त्यौहारों के समय, जब भी साम्प्रदायिक तनाव होते हैं। वे संघर्ष में बदल जाते हैं। पहले तो एक-दूसरे की जान लेने की कोशिश की जाती है उसमें सफल न होने पर लोगों की व्यक्तिगत सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है। तनाव एवं संघर्ष के अधिक बढ़ जाने पर सारा दोष सरकार पर थोप दिया जाता है और सरकारी संपत्ति को हानि पहुँचायी जाती है। साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान अक्सर सरकारी वाहनों, रेलगाड़ियों में तोड़-फोड़ एवं जलाने की घटना देखी जाती है।

3. देश की एकता एवं अखंडता को खतरा (Challenges of Unity and Integrity of the Country) – साम्प्रदायिक तनाव एवं संघर्ष के दौरान विविध समुदायों के बीच हिंसक घटनाएं जन्म लेती हैं जिससे देश की एकता एवं अखंडता भी प्रभावित होती है। साम्प्रदायिक गतिविधियों (Communal Activities) के तहत कुछ लोग देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल हो जाते हैं। भारत में आतंकी घटनाएं भी अप्रत्यक्ष रूप से सांप्रदायिकता के कारण उत्पन्न हो रही हैं जोकि देश की एकता एवं अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भारत में संसद पर हमला, विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं पर आतंकी कार्यवाही देश की संप्रभुता-एकता एवं अखंडता को चुनौती दे रही है।

पंजाब में खालिस्तान की माँग हो अथवा आजाद कश्मीर का मुद्दा हो। मुख्यतः यह धर्म आधारित माँग थी। इसी तरह नागालैंड में ईसाईयों द्वारा पृथक राज्य की स्थापना की माँग भी मुख्यतः धार्मिक निष्ठा पर ही आधारित थी।

4. आर्थिक विकास, धर्मनिरपेक्षीकरण एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया दुष्प्रभावित – साम्प्रदायिक संघर्ष के दौरान प्रभावित क्षेत्र की सामान्य गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं साथ ही, सरकार द्वारा चलाए जाने वाले आर्थिक विकास संबंधी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी सामान्य रूप से नहीं हो पाता है। वस्तुतः साम्प्रदायिक संघर्ष के दौरान लोग सरकारी तंत्र पर हमला बोल देते हैं तथा भौतिक संसाधनों एवं मशीनरी को तो नष्ट करने का प्रयास करते हैं साथ ही, सरकारी संस्थाओं में कार्यरत लोगों के प्रति भी हिंसक व्यवहार करते हैं जिसके कारण हिंसा प्रभावित क्षेत्र में कोई कर्मचारी एवं अधिकारी जाना नहीं चाहता। विकास कार्यक्रम (Development Programme) के क्रियान्वयन के अभाव के परिणाम स्वरूप उस समाज का तो आर्थिक विकास रुकता ही है, राष्ट्र की आर्थिक विकास (Economic Development) की गतिविधियों पर भी चोट पहुँचती है। परिणामतः देश का आर्थिक विकास रुक जाता है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया रुकने के पश्चात् भारतीय समाज में आधुनिकीकरण (Modernization) की प्रक्रिया पर भी प्रश्नचिह्न लग जाता है क्योंकि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आर्थिक विकास का परिणाम होती है इसके अलावा सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुधार संबंधी कानूनों के निर्माण एवं क्रियान्वयन को भी साम्प्रदायिक भावना के कारण अवरुद्ध किया जाता है, जिससे आधुनिक समाज के निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है। शाहबानों प्रकरण एवं समान आचार संहिता के भारत में न लागू हो पाने के साम्प्रदायिक कारणों को आधुनिकीकरण एवं महिला विकास में बाधा के रूप में स्पष्टतः समझा जा सकता है।

5. राजनीतिक अस्थिरता (Political Instability) – भारतीय समाज में साम्प्रदायिक समस्या के परिणामस्वरूप उपजे सामाजिक एवं सामुदायिक संघर्ष के बाद सामान्य सामाजिक जीवन में कठिनाईयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। कभी-कभी सवैधानिक तंत्र भी फेल हो जाता है जिसके कारण राजनीतिक प्रक्रिया में भी बाधा उत्पन्न हो जाती है। हिंसा ग्रस्त क्षेत्र में अक्सर चुनाव कराना कठिन हो जाता है (जम्मू-कश्मीर) और लोकतांत्रिक प्रणाली को चोट पहुँचती है। कभी-कभी सरकारें भी साम्प्रदायिक ताकतों को परोक्ष रूप से सहयोग देती हैं और साम्प्रदायिक संघर्ष (Communal Conflict) को बढ़ावा देती हैं जिसके कारण वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता है। इन सभी उदाहरणों को भारतीय समाज में अक्सर देखा जाता है जिससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है।

6. असामाजिक तत्वों एवं विचलित व्यवहारों में वृद्धि (Increase of Anti Social Elements and Deviant behaviours) – भारतीय समाज में साम्प्रदायिक संघर्ष के दौरान अक्सर हिंसक घटनाएँ बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में असामाजिक तत्वों को भी अपनी गतिविधि संचालित करने का मौका मिल जाता है। मौके का फायदा उठाकर अपराधी लोग समाज में अपने क्रिया-कलापों को अंजाम देते रहते हैं। इसके अलावा संघर्ष एवं हिंसा की स्थिति में महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध की संख्या बढ़ जाती है सामान्य व्यक्ति भी कभी-कभी परिस्थितिवश विचलित व्यवहार करने लगते हैं। हिंसा के दौरान लोग इसी बहाने अपनी दुश्मनी निकालने लगते हैं जिससे हिंसा और बढ़ जाती है।

भारत में सांप्रदायिकता निवारण हेतु किए गए प्रयास (Efforts made to Prevent Communalism in India)

भारतीय समाज में सांप्रदायिकता निवारण हेतु सर्व-धर्म-समभाव की प्रवृत्ति विचारकों में पहले से ही रही है, जिसके लिए विभिन्न समाज सुधारक समय-समय पर प्रयास करते रहे हैं। आजादी के आंदोलन के समय गांधी जी एवं अन्य राष्ट्रीय नेताओं द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर सांप्रदायिकता के उन्मूलनार्थ प्रयास किए जाते रहे हैं, जिसे आजादी के बाद सरकारी स्तर पर किया जाने लगा। स्वतंत्रता के पश्चात् किए गए प्रमुख प्रयासों को निम्नवत समझा जा सकता है:-

1. अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 1978 में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई। आगे चलकर 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा देते हुए इसका नामकरण राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कर दिया गया।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग पांच समुदायों, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सिख के कल्याण हेतु उपाय सुझाता है तथा उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व इस आयोग को दिया गया है (केन्द्र सरकार द्वारा 2014 में जैन समुदाय को छठे अल्पसंख्यक के रूप में नामित किया गया)।
2. साम्प्रदायिक समस्याओं पर विचार करने तथा विविध अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित रखने एवं सामाजिक सौहार्द (Social Harmony) बनाए रखने को उत्प्रेरित करने के लिए 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई है, जिसे समय-समय पर सक्रिय किया जाता रहा है।
3. 1976 में ब्रह्मानंद रेड्डी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकीकरण पर गठित कार्यदल द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द का कार्यक्रम बनाया गया है।

4. भारत सरकार में भाषायी एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के कल्याण की आवश्यकता पर जोर दिया है।
5. धार्मिक एवं भाषायी अल्प संख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं को खोलने एवं अपनी भाषा एवं संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार दिया है।
6. विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं जैसे शांति, अखंड भारत आदि द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द (Communal Harmony) के लिए विभिन्न क्रिया-कलाप किए जा रहे हैं।
7. देश के विभिन्न राज्यों में साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए विविध अभियान चलाए जा रहे हैं।
8. भाषायी अल्पसंख्यकों (Linguistic Minority) के हितों के सुरक्षार्थ भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त के पद का सृजन किया गया है। यह भाषायी अल्पसंख्यकों से जुड़ी राष्ट्रीय एवं वैधानिक योजनाओं के लागू न किए जाने संबंधी शिकायतों का निबटारा करता है।
9. समाज के शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना की गई है जिसने अल्पसंख्यकों के बीच सद्भावना बढ़ाने का कार्य किया है, प्रतिभावान छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ देता है और साक्षरता में वृद्धि के लिए साक्षरता कार्यक्रम चलाता है।

मूल्यांकन (Evaluation)

बहुलवादी भारतीय समाज (Pluralistic Indian Society) में विविध समुदायों के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ-साथ नकारात्मक प्रतिक्रियाएँ भी चलती रही हैं, जिनके विविध कारण एवं संयुक्त परिणाम रहे हैं। इस नकारात्मक प्रतिक्रिया (सांप्रदायिकता) के समाधान हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर विविध प्रयास किए गए हैं और उन प्रयासों का कुछ हद तक सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप साम्प्रदायिक संघर्ष में कुछ कमी की संभावनाएँ बढ़ी हैं। स्वतंत्रता पूर्व एवं भारत के बँटवारे के समय गांधी जी एवं अन्य राष्ट्रीय नेताओं द्वारा किए गए प्रयास साम्प्रदायिक समस्या को रोकने में काफी हद तक सफल रहे, जिसके कारण दंगे एवं हिंसा में कमी आई थी।

राष्ट्रीय एकीकरण पर गठित कार्यदल द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए किया गया प्रयास काफी हद तक सराहनीय रहा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना से अल्पसंख्यकों की समस्याओं एवं उनके असंतोष काफी हद तक स्पष्ट हो गए हैं जिनको दूर करने के लिए प्रयास भी किए जाने लगे हैं। विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों द्वारा किए गए साम्प्रदायिक सौहार्द

संबंधी गतिविधियाँ भी विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समझ बढ़ाने एवं उनको एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया है। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउन्डेशन द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द्र बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों का तो सकारात्मक प्रभाव पड़ा ही है, साथ ही अल्पसंख्यकों में पिछड़ों में छात्रवृत्तियाँ देने एवं साक्षरता अभियान चलाने से विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आधुनिक शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी है (जबकि परंपरागत मुस्लिम मदरसा शिक्षा को महत्व देते रहे हैं जो कि विविध धर्मावलाम्बियों के प्रति रूढ़िवादी विचारधारा से प्रेरित रही है) जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक विचार के पोषण एवं राष्ट्रीय भावना के जागरण से इनके बीच अन्य धर्म के लिए शंका एवं वैमनस्य में कमी आने की संभावना बढ़ी है।

उपरोक्त प्रयासों से यद्यपि साम्प्रदायिक समस्या में कमी आने की संभावना बढ़ी है किन्तु इन्हें पूरी तरह सफल नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन प्रयासों के बावजूद भी आज सांप्रदायिकता भारतीय समाज की प्रमुख सामाजिक समस्या बनी हुई है।

मुजफ्फरनगर दंगा, बाबरी मस्जिद कांड, गोधरा कांड की प्रतिक्रिया में गुजरात में हुए दंगे, मऊ का दंगा या इलाहाबाद में 'कुरान' फाड़ने पर उभरा साम्प्रदायिक तनाव ऐसे उदाहरण हैं जो उपरोक्त प्रयासों की अपर्याप्तता को परिलक्षित करते हैं। उपरोक्त कमियों के आलोक में निम्न कारक जिम्मेदार रहे हैं:—

1. आज भी मुस्लिम समुदाय एवं हिन्दू समाज में आधुनिक शिक्षा की भावना विकसित नहीं हो पायी है और वह अन्य समुदायों के प्रति शंका से प्रेरित रहती है जो राजनीतिक लाभ के कारण वास्तविक समस्याओं की ओर कम महत्व देती है जिससे उनके भीतर आधुनिक दृष्टिकोण एवं अन्य धर्म के प्रति संकीर्ण नजरिया अपनाते हैं।
2. अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना एवं उसमें नियुक्तियाँ राजनीतिक होने के कारण वह अपने वास्तविक उद्देश्यों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं।
3. विभिन्न स्वयं सेवी संगठन आर्थिक लाभ के लिए कार्य करते हैं तथा वास्तविक समस्या पर ध्यान नहीं देते हैं।
4. गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, असमानता आदि कारक आज भी साम्प्रदायिक समस्या को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। धर्मस्थ राजनीति ने भारत में साम्प्रदायिक समस्या को और उत्प्रेरित किया है।
5. ऐसे धार्मिक संस्थाओं की पहचान की जाए जो साम्प्रदायिक गतिविधियों में संलग्न हैं, उन्हें प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
6. धर्मनिरपेक्षता को सशक्त विचारात्मक स्तर पर जन आंदोलन का रूप दिया जाए और इसके पक्ष में जनचेतना और जनमत निर्मित किये जाने का प्रबल प्रयास करना चाहिए।
7. राष्ट्रीयता या हम सब एक हैं की भावना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
8. ईमानदार शैक्षिक एवं सांस्कृतिक नीति का अनुपालन (Compliance) किया जाए, जिससे साम्प्रदायिक वर्गों के मध्य परस्पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान संभव हो सके।
9. परस्पर अविश्वास एवं विद्वेष की भावना को समाप्त करने के लिए अल्पसंख्यकों के मन से असुरक्षा की भावना को कम किये जाने का प्रयास किया जाय।
10. मुस्लिमों की वास्तविक समस्याओं (रोजगार, गरीबी, साक्षरता आदि) का समुचित समाधान किया जाय (सच्चर समिति की रिपोर्ट)।
11. दोष निवारक उपायों, पुलिस व न्याय व्यवस्था को दुरुस्त तथा अधिक सक्रिय बनाया जाय।
12. दंगों से पीड़ितों को तत्काल सहायता पहुँचाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था निर्मित की जाय।
13. मीडिया की भूमिका को सकारात्मक स्वरूप प्रदान किये जाने का प्रयास भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

स्पष्ट है कि सांप्रदायिकता एवं साम्प्रदायिक हिंसा भारतीय समाज की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम है। धर्म से अधिक साम्प्रदायिक दुष्प्रचार, अफवाह तथा साम्प्रदायिक लामबंदी इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। हाल के वर्षों में भूमंडलीकरण से उत्पन्न पहचान का संकट, धार्मिक कट्टरवाद और धर्म का बाजारीकरण भी सांप्रदायिकता हेतु सहयोगी रहे हैं। भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की सफलता तभी साकार हो सकती है जब इस समस्या का उन्मूलन कर दिया जाए, जो कि उपरोक्त सुझावों पर अमल करके तथा मीडिया, आधुनिक शिक्षा और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के सहयोग से सांप्रदायिकता के विरुद्ध एक जन आंदोलन के द्वारा ही संभव है।

भारत में सांप्रदायिकता : संभावित प्रश्न

अतः इसके लिए कुछ एक अन्य उपायों / सुझावों पर विचार किया जा सकता है:—

1. साम्प्रदायिक मानसिकता वाले राजनीतिज्ञों, दलों तथा व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जाए और उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।
2. वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने क्षेत्रवादी भावना के उभार को किस प्रकार प्रोत्साहित किया है? स्पष्ट करें।
3. क्षेत्रवाद की समस्या लोकतंत्र की असफलता को सिद्ध करती है तथा इसका बेहतर समाधान लोकतंत्र के विस्तार द्वारा ही संभव है। स्पष्ट करें।

3. छोटे राज्यों का गठन क्षेत्रीय विषमता को दूर करने में कहाँ तक प्रासंगिक है? समीक्षा करें।
4. भारत में आधुनिकता के विस्तार ने धर्मनिरपेक्षता के समक्ष किन नवीन चुनौतियों को पेश किया है? चर्चा करें।
5. भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा इसके सामाजिक विशेषताओं को प्रतिबिंबित करती है। स्पष्ट करें।
6. प्रस्तावित साम्प्रदायिक हिंसा विरोधी विधेयक के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करें। साम्प्रदायिक हिंसा रोकने हेतु इसके उपादेयता की समीक्षा करें।
7. सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों की उपस्थिति सांप्रदायिकता का प्रमुख कारण है?
8. सांप्रदायिकता राजनीति एवं धर्म का एक अवैध गठबंधन है। समीक्षा करें।
9. सांप्रदायिकता लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में किस तरह के अवरोध पैदा करता है? सांप्रदायिकता की समस्या के हल हेतु अपने सुझाव दें।
10. राष्ट्रीय एकीकरण हेतु क्षेत्रवाद एवं राष्ट्रवाद का संतुलन आवश्यक है, चर्चा करें।

